खंड . 3 अंक . 12 जुलाई 2021

1945 से राष्ट्र सेवा में समर्पित

जलांश

केंद्रीय जल आयोग का मासिक सूचना पत्र

संदेश

एस के हालदार
अध्यक्ष, के.ज.आ.

केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 15.06.2021 को देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा और बारहमासी बाढ़ की समस्याओं को एक व्यापक नीति द्वारा कम करने के लिए दीर्घकालिक उपायों के लिए एक बैठक की गई। इसमें जल शक्ति मंत्री, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), विभाग और के.ज.आ. के अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। बैठक में, मैंने दिनांक 03.07.2020 की बैठक में माननीय गृह मंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों के संदर्भ में विभाग/ के.ज.आ. द्वारा की गई कार्रवाई पर एक प्रस्तुति दी। अपनी प्रस्तुति में, मैंने संक्षेप में बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी), के.ज.आ. के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष के कामकाज और सभी जलाशयों के लिए के.ज.आ. द्वारा 5 दिवसीय अग्रिम प्रवाह पूर्वानुमान और अन्य पहलों के बारे में बताया। विभिन्न लंबित भारत-नेपाल परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की स्थिति और असम में बारहमासी बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन में भंडारण परियोजनाओं की आवश्यकता पर भी मेरी प्रस्तुति के दौरान प्रकाश डाला गया।

इसके बाद, के.ज.आ. द्वारा विभाग की व्यापक आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) 23.06.2021 को एनडीएमए को प्रस्तुत की गई थी। एनडीएमए के सदस्यों ने व्यापक डीएमपी दस्तावेज़ की सराहना की और योजना में शामिल करने के लिए कुछ अतिरिक्त सुझाव दिया।

उत्तराखंड में फरवरी, 2021 की आकस्मिक बाढ़ की घटना ने हिमनद झीलों की कुशल निगरानी की आवश्यकता पर और बल दिया। यह मामला अब जल संसाधन संबंधी संसदीय स्थायी समिति और सरकार के सभी हितधारक एजेंसियों के सक्रिय विचार-विमर्श में है। एक उल्लेखनीय विकास के अंतर्गत, एनआरएससी ने जून, 2021 में गंगा बेसिन के हिमनद झीलों का एटलस बनाया है। अध्ययन में, कुल 4,707 हिमनद झीलों का मानचित्रण किया गया है, जिनका फैलाव 0.25 हेक्टेयर से अधिक है। सिंधु बेसिन के लिए अद्यतन सूची भी दिसंबर, 2020 में प्रकाशित की गई थी। के.ज.आ. में सिंधु और गंगा नदी घाटियों के लिए ग्लेशियल लेक डेटाबेस (0.25 हेक्टेयर से अधिक) प्राप्त हो चुका है और इसका उपयोग हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों की निगरानी में किया जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) और सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन परिषद (सीईडीसी) की विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से के.ज.आ. जल संसाधन विकास और प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्र में मानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मैंने हाल ही में डब्ल्यूआरडीसी की 20वीं बैठक की अध्यक्षता की। इसके अलावा, के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूआरडीसी की 17 अनुभागीय समितियों और सीईडीसी की 13 अनुभागीय समितियों में मुख्य अभियंता और निदेशक स्तर के अधिकारियों द्वारा किया जाता है।

विषय वस्तु

- आगामी बाढ़ सीजन की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक
- माननीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा
- पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की ई-बुक का विमोचन
- रिवर इंटरलिंकिंग की समीक्षा
- स्काडा सिस्टम्स का उपयोग कर नहर स्वचालन पर चर्चा के संबंध में बैठक
- सातवें भारत जल सप्ताह- 2021 की आयोजन समिति की तीसरी बैठक
- तिलैया-धाधर डायवर्जन योजना के संबंध में बैठक
- बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा
- गंगा बेसिन हिमनद झील एटलस का विमोचन
- बीआईएस की जल संसाधन मंडल परिषद की 20वीं बैठक
- राजस्थान और सरहिंद फीडर के रिलाइनिंग के कार्यों की स्थिति की समीक्षा
- सदस्य(डबल्यूपी&पी), के.ज.आ. को आईडबल्यूआरएस पुरस्कार
- जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना
- देश में बाढ़ की स्थिति
- एनएचपी के तहत के.ज.आ. की गतिविधियां और प्रगति
- ड्रिप
- एनडब्ल्यूडीए के साथ डीवीजी और डीईजी लिंक के संबंध में वर्चुअल बैठकें
- डेटा कॉर्नर- 1955-2015 की अवधि के दौरान वर्षा के तुलनात्मक आंकड़े
- जलाशय निगरानी
- प्रशिक्षण/उच्च अध्ययन
- इतिहास- केआरएस बांध

आगामी बाढ़ के मौसम की तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक

देश में बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों के उपायों की समीक्षा के लिए और देश की बारहमासी बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए व्यापक और विस्तृत नीति के लिए दीर्घकालिक उपायों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा 15.06.2021 को एक बैठक की गई । इसमें माननीय जल शक्ति मंत्री, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग), अध्यक्ष, के.ज.आ., विभाग के अपर सचिव , आयुक्त (एफएम) और निदेशक (एफएफएम), के.ज.आ. ने भाग लिया।

अध्यक्ष, के.ज.आ. ने दिनांक 03.07.2020 की बैठक में माननीय गृह मंत्री के निर्देशों के संबंध में की गई कार्रवाई पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने बाढ़ की रोकथाम के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक उपायों, बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी) के बारे में बताया, जिसमें 2021-26 की अवधि के लिए 15,000 करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय है और के.ज.आ. के केंद्रीय बाढ़ नियंत्रण कक्ष का 24X7 आधार पर संचालन शामिल है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि के.ज.आ. और गूगल ने अब बाढ़ चेतावनी डैशबोर्ड लॉन्च किया है और बाढ़ पूर्वानुमान जारी करना शुरू कर दिया है। उन्होंने आगे विभिन्न लंबित भारत-नेपाल परियोजनाओं से संबंधित मुद्दों की स्थिति और असम में बारहमासी बाढ़ की समस्याओं को कम करने के लिए ब्रह्मपुत्र बेसिन में भंडारण परियोजनाओं की आवश्यकता के बारे में बताया। उन्होंने जलग्रहण क्षेत्र में आईएमडी के वर्षा पूर्वानुमान के आधार पर देश के सभी जलाशयों के लिए के.ज.आ. द्वारा 5 दिवसीय अग्रिम प्रवाह पूर्वानुमान, एकीकृत जलाशय संचालन और बांध सुरक्षा विधेयक के लाभों के बारे में भी जानकारी दी, जो राज्यसभा में विचार के लिए लंबित है।

उपरोक्त बैठक की प्रस्तावना के रूप में, माननीय जल शक्ति मंत्री ने एक समीक्षा बैठक आयोजित की जिसमें विभाग/ के.ज.आ. के संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। केंद्रीय गृह मंत्री के साथ बैठक की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में, के.ज.आ. आईएमडी और एनडीआरएफ के समन्वय में गृह मंत्रालय को दैनिक बाढ़ पूर्वानुमान सलाह जारी कर रहा है।

माननीय मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा

माननीय मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा सभी राष्ट्रीय परियोजनाओं (पोलावरम सिंचाई परियोजना को छोड़कर) की समीक्षा के लिए 16.06.2021 को एक बैठक आयोजित की गई थी। जल शक्ति मंत्रालय, केंद्रीय जल आयोग, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी और ऊपरी यमुना नदी बोर्ड के अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। समीक्षा के दौरान, वर्तमान स्थिति, परियोजनाओं को पूरा करने की योजना और बाधाओं सहित परियोजना-वार चर्चा की गई। इन परियोजनाओं (यानी सरयू नहर परियोजना, गोसीखुर्द परियोजना और शापुरकंडी बांध परियोजना) को जल्द से जल्द पूरा करने की संभावनाएं हैं, उनके पूरा होने में तेजी लाने के लिए व्यापक रूप से चर्चा की गई। माननीय मंत्री ने उपरोक्त तीन चल रही राष्ट्रीय परियोजनाओं की उप-घटक-वार बाधाओं का पता लगाने के.ज.आ. के संबंधित मुख्य अभियंताओं और राज्य सरकार के अधिकारियों को दौरे का निर्देश दिया ताकि उक्त परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संभावित मुद्दों/अड़चनों को दूर करने के लिए कार्रवाई की जा सके। कुलसी और नोआ दिहिंग परियोजनाओं के मामले में, जो के.ज.आ. में मूल्यांकन के उन्नत चरण में हैं, माननीय मंत्री महोदय ने इस मामले को क्रमशः असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की सरकार के साथ आगे बढ़ाने का सुझाव दिया। इन पूर्वोत्तर राज्यों को विभाग के बी एंड बी विंग द्वारा दिनांक 02.07.2021 को पत्र भेजे गए थे।

16.06.2021 को माननीय जल मंत्री द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं की समीक्षा के परिणामस्वरूप, प्रगति पर नज़र रखने और परियोजनाओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण गतिविधियों और बाधाओं को दूर करने के लिए, निम्नलिखित परियोजनाओं का दौरा किया गया:

- मुख्य अभियंता, सिंधु बेसिन संगठन, चंडीगढ़, के.ज.आ. द्वारा 25.06.2021 को शाहपुर कंडी परियोजना, पंजाब
- सरयू नहर परियोजना, उत्तर प्रदेश 23 और 24 जून, 2021 को मुख्य अभियंता (यूजीबीओ), के.ज.आ., लखनऊ द्वारा निदेशक (एम एंड ए), के.ज.आ., लखनऊ और एईई, के.ज.आ., लखनऊ के साथ
- 24.06.2021 से 26.06.2021 के दौरान मुख्य अभियंता, निगरानी केंद्रीय संगठन, के.ज.आ., नागपुर ने गोसीखुर्द सिंचाई परियोजना, महाराष्ट्र का दौरा किया

राष्ट्रीय परियोजनाओं का दौरा

के.ज.आ. द्वारा जल गुणवत्ता गतिविधि से संबंधित विभिन्न बिंदुओं और मुद्दों के संबंध में माननीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष प्रस्तुति

के.ज.आ. द्वारा की जा रही जल गुणवत्ता गतिविधियों का महत्व दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। के.ज.आ. एकमात्र केंद्रीय एजेंसी है जिसके पास पानी की गुणवत्ता के लिए नमूनों का विश्लेषण करने के लिए अपनी सतही जल नमूना संग्रह प्रणाली और प्रयोगशालाएं हैं। के.ज.आ. द्वारा तैयार किए जा रहे जल गुणवत्ता डेटा और रिपोर्ट का उपयोग एनएमसीजी, सीपीसीबी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) जैसी विभिन्न एजेंसियों द्वारा किया जा रहा है।

के.ज.आ. के विभिन्न जल गुणवत्ता पहलुओं पर चर्चा के लिए दिनांक 14.06.2021 को माननीय जल मंत्री द्वारा एक बैठक की गई। सीपीसीबी के नदी के पानी को वर्गीकृत करने के ए, बी, सी, डी और ई मानदंड के आधार पर कुछ महत्वपूर्ण नदियों के 8 महत्वपूर्ण मापदंडों पर नदियों के अनुदैर्ध्य प्रोफाइल के साथ जल गुणवत्ता के दीर्घकालिक प्रवृत्ति विश्लेषण पर एक प्रस्तुति दी गई थी । माननीय मंत्री ने के.ज.आ. को नदियों में पानी की गुणवत्ता की स्थिति का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक अधिक समावेशी विश्लेषण और व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी की ई-बुक का विमोचन

जल संरक्षण और इसके प्रबंधन को उच्च प्राथमिकता देने के लिए भारत सरकार की प्रतिबद्धता को जारी रखते हुए, प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को सिंचाई के विस्तार हेतू इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया था की "हर खेत को पानी" मिले और और जल उपयोग दक्षता में सुधार हो अर्थात "प्रति बूंद अधिक फसल" हो। पीएमकेएसवाई को पहले से चल रही योजनाओं- त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (AIBP), एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) और ऑन-फार्म जल प्रबंधन (OFWM) को मिलाकर तैयार किया गया है।

माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 17.06.2021 को पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत किए गए प्रयासों और उपलब्धियों को दर्शाने वाली एक ई-बुक का विमोचन किया गया। विमोचन के दौरान माननीय राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया, विभाग के अधिकारी एवं केन्द्रीय जल आयोग के अधिकारी उपस्थित थे।

विमोचन के दौरान माननीय मंत्री ने बताया कि एआईबीपी के

तहत 99 परियोजनाओं में से 44 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि लगभग 20 परियोजनाओं की प्रगति 90% से अधिक है और अतिरिक्त 12 परियोजनाओं की प्रगति 80-90% के बीच है। पूर्ण हो चुकी परियोजनाओं ने 21 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया है, जिससे किसानों की आय में वृद्धि कर उनके जीवन को बदलने में मदद मिली है।

इस ई-बुक को निम्न लिंक से प्राप्त किया जा सकता है।

http://pmksy-mowr.nic.in/aibp-mis/Manual/PMKSY_CTB_ebook/mobile/index.html

रिवर इंटरलिंकिंग की समीक्षा

माननीय जल शक्ति मंत्री ने, सचिव (जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग) और के.ज.आ. / एनडब्ल्यूडीए के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में रिवर इंटरलिंकिंग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। श्री श्रीराम वेदिरे, सलाहकार, जल शक्ति मंत्रालय और महानिदेशक, एनडब्ल्यूडीए ने प्राथमिकता वाले लिंक जैसे केन-बेतवा, दमनगंगा-पिंजाल, पर-तापी-नर्मदा, मानस-संकोश-तिस्ता-गंगा, गंगा-दामोदर-सुवर्णरेखा, महानदी-गोदावरी, गोदावरी-कावेरी और राजस्थान के ईआरसीपी के साथ संशोधित पीकेसी परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति पर एक प्रस्तुति दी।

स्काडा सिस्टम्स का उपयोग कर नहर स्वचालन(कैनल ऑटोमेशन) पर चर्चा के संबंध में बैठक

माननीय जल शक्ति मंत्री द्वारा 24.6.2021 को "स्काडा का उपयोग कर नहर स्वचालन" पर एक ब्रीफिंग बैठक ली गई थी। श्री एस. के. हलदर, अध्यक्ष, के.ज.आ.; श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. और श्री योगेश पैठंकर, मुख्य अभियंता(पीएओ), के.ज.आ. ने 'नहरों के आधुनिकीकरण' के संदर्भ और प्रासंगिकता पर एक प्रस्तुति दी। इसके बाद डॉ. एम. सेल्वा बालन, वैज्ञानिक ई, सीडब्ल्यूपीआरएस, पुणे द्वारा 'नहरों के स्वचालन' पर एक प्रस्तुति दी गई। श्री आर. राम, मुख्य अभियंता, केबीजेएनएल, कर्नाटक और एडीबी के श्री राजेश यादव भी वर्चुअल मोड के माध्यम से उपस्थित थे।

इस संबंध में किए गए पहले के प्रयासों सहित नहर आधुनिकीकरण की चुनौतियों और आवश्यकता पर विस्तृत चर्चा

के बाद, माननीय जल शक्ति मंत्री ने कर्नाटक में नारायणपुर लेफ्ट बैंक कैनाल (एनएलबीसी) परियोजना स्थल पर किए गए कार्यों और उनकी प्रभावशीलता और उस पर किसानों की प्रतिक्रिया का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने के लिए परियोजना स्थल का दौरा करने की इच्छा व्यक्त की।

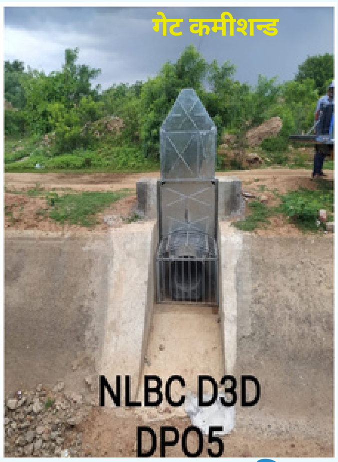

सातवें भारत जल सप्ताह- 2021 की आयोजन समिति की तीसरी बैठक

7वें भारत जल सप्ताह-2021 की आयोजन समिति की तीसरी बैठक श्री पंकज कुमार, सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय और अध्यक्ष, आयोजन समिति आईडब्ल्यूडब्ल्यू- 2021 की अध्यक्षता में 03.06.2021 को आयोजित की गई। समिति ने आईडब्ल्यूडब्ल्यू-2021 के आयोजन की प्रगति की समीक्षा की और कोविड -19 महामारी परिदृश्य को देखते हुए आसन्न गतिविधियों पर विचार-विमर्श किया। विभिन्न विकल्पों को ध्यान में रखते हुए, समिति ने सिफारिश की कि या तो 7वें भारत जल सप्ताह को वर्ष 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया जाए या 16-20 नवंबर 2021 से निर्धारित कार्यक्रम को वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाए। समिति ने अंतिम निर्णय लेने के लिए यह सिफारिश माननीय जल शक्ति मंत्री के समक्ष प्रस्तुत की। समिति ने निर्णय लिया कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2021 को ध्यान में रखते हुए ब्रिक्स जल मंत्रियों की बैठक और ब्रिक्स जल मंच को 16-17 नवंबर 2021 को निर्धारित समय के अनुसार हाइब्रिड/वर्चुअल मोड में उस समय की परिस्थितियों के अनुसार आयोजित किया जा सकता है।

तिलैया-धाधर डायवर्जन योजना के संबंध में बैठक

तिलैया-धाधर डायवर्जन योजना के जल बंटवारे के विवाद पर चर्चा करने के लिए सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में 21.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रमुख सचिव, डब्ल्यूआरडी, बिहार सरकार और सचिव, डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, संयुक्त सचिव व अन्य अधिकारियों ने भाग लिया। । अध्यक्ष, के.ज.आ.; सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी) और मुख्य अभियंता (आईएमओ) ने के.ज.आ. की ओर से बैठक में भाग लिया। अध्यक्ष ने जोर दिया कि दोनों राज्यों को न्यायिक निहितार्थ से बचने के लिए विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करना चाहिए।

बिहार और झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना की समीक्षा

परियोजना की प्रगति की समीक्षा करने और बिहार तथा झारखंड में उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना के लंबित मुद्दों को हल करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से 23.06.2021 को सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। विभाग ,के.ज.आ. (मुख्यालय), बिहार और झारखंड राज्य सरकारों और वैपकोस के अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में भाग लिया। मुख्य अभियंता (आईएमओ), के.ज.आ. और सदस्य-सचिव, तकनीकी मूल्यांकन समिति (टीईसी) ने बैठक में चर्चा के लिए विभिन्न एजेंडा बिंदुओं पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी। प्रत्येक एजेंडा आइटम पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

सचिव महोदय ने सचिव, डब्ल्यूआरडी, झारखंड सरकार और

मुख्य अभियंता (पी एंड एम) पटना, डब्ल्यूआरडी बिहार से लक्ष्य के अनुसार परियोजना को पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए लंबित मुद्दों को तेजी से हल करने का अनुरोध किया।

गंगा बेसिन हिमनद झील एटलस का विमोचन

सचिव, जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग ने 29.06.2021 को एक वर्चुअल इवेंट में अंतरिक्ष विभाग के सचिव और इसरो के अध्यक्ष, डॉ के सिवन और जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, अंतरिक्ष विभाग, राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) और राज्य सरकार प्राधिकरण के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में गंगा बेसिन के हिमनद झील एटलस को जारी किया। वर्तमान हिमनद झील एटलस गंगा नदी बेसिन के ऊपरी भाग से हिमालय की तलहटी में 2,47,109 वर्ग किमी के जलग्रहण क्षेत्र को शामिल करने वाली हिमनद झीलों पर आधारित है। गंगा नदी बेसिन के अध्ययन किए जाने वाले भाग में भारत का हिस्सा और सीमा पार क्षेत्र शामिल हैं। एटलस, एनआरएससी, इसरो के भुवन पोर्टल (https://bhuvan.nrsc.gov.in/nhp/), इंडिया डब्ल्यूआरआईएस पोर्टल (www.indiawris.gov.in) और विभाग की एनएचपी वेबसाइट (www.nhp.mowr.gov.in)

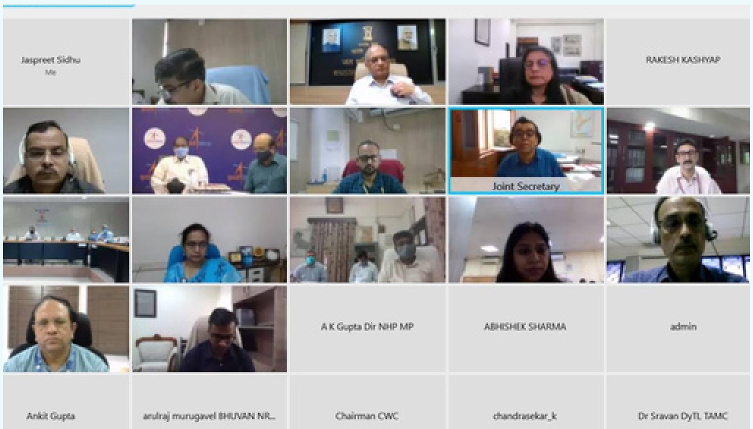

पर उपलब्ध है।

के.ज.आ. में सिंधु और गंगा नदी घाटियों के लिए ग्लेशियल लेक डेटाबेस (0.25 हेक्टेयर से अधिक) प्राप्त किया गया है और इसका उपयोग हिमालयी क्षेत्र में हिमनद झीलों की निगरानी में किया जाएगा।

फरक्का बैराज के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन समिति की तीसरी बैठक

"बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन" समिति की तीसरी बैठक अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में 08.06.2021 को आयोजित की गई । बैठक में बिहार सरकार और एनआईएच, पटना के अधिकारियों और के.ज.आ. और जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की समिति के अन्य सदस्यों ने भाग लिया। निदेशक, जल विज्ञान (मध्य), के.ज.आ. ने 05.02.2021 को हुई पिछली बैठक के बाद के घटनाक्रम से अवगत कराया। आरएमएसआई के प्रतिनिधियों ने प्रस्तुत इंसेप्शन रिपोर्ट पर एक प्रस्तुति दी और अनुरोधित डेटा की स्थिति प्रस्तुत की। समिति के सदस्यों से इनपुट के आधार पर, अध्यक्ष, के.ज.आ. ने संबंधित हितधारकों को इस संबंध में डेटा संग्रह में तेजी लाने के निर्देश दिए।

आपदा प्रबंधन पर स्थायी समिति की पहली बैठक

आपदा प्रबंधन पर नवगठित स्थायी समिति (एससी-डीएम) की पहली बैठक 23.06.2021 को सदस्य सचिव, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) की अध्यक्षता में वर्चुअल मोड में आयोजित की गई । आपदा प्रबंधन क्षेत्र में अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग को सक्षम करने के लिए आपदा प्रबंधन स्थायी समिति (एससी-डीएम), अंतरिक्ष अनुप्रयोग प्रबंधन प्रणाली (एसएएमएस) की एक समिति है। बैठक में अध्यक्ष, के.ज.आ. ने सदस्य (आरएम) और निदेशक (एफएफएम), के.ज.आ. के साथ भाग लिया। अध्यक्ष, के.ज.आ. ने इसरो से 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्र के हिमनद झीलों और जल निकायों का मानचित्रण करने का अनुरोध किया और मानचित्रण करने में सक्षम बनाने के लिए के.ज.आ. के साथ सहयोग का भी अनुरोध किया। उन्होंने प्रासंगिक उपग्रह डेटा मुफ्त में उपलब्ध कराने का भी सुझाव दिया।

बीआईएस की जल संसाधन मंडल परिषद की 20वीं बैठक

जल संसाधन क्षेत्र में एक शीर्ष तकनीकी निकाय होने के नाते के.ज.आ., भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के जल संसाधन प्रभाग परिषद (डब्ल्यूआरडीसी) और सिविल इंजीनियरिंग डिवीजन काउंसिल (सीईडीसी) की विभिन्न गतिविधियों में अपनी भागीदारी के माध्यम से जल संसाधन विकास, प्रबंधन और संबद्ध क्षेत्रों में मानकों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। । अध्यक्ष, के.ज.आ. वर्तमान में डब्ल्यूआरडीसी के अध्यक्ष हैं। डब्ल्यूआरडीसी की 20वीं बैठक 29.06.2021 को श्री एस के हालदार, अध्यक्ष, के.ज.आ. की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। के.ज.आ. का प्रतिनिधित्व डब्ल्यूआरडीसी की 17 अनुभागीय समितियों और सीईडीसी की 13 अनुभागीय समितियों द्वारा किया गया।

अनुभागीय समिति-डब्ल्यूआरडी 05 की बैठक: "सुरंगों के लिए भूवैज्ञानिक अन्वेषण - दिशानिर्देश" का मसौदा

कोविड-19 प्रोटोकॉल के मद्देनजर 21.06.2021 को वीडियो कांफ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से एक बैठक आयोजित की गई। यह सुरंग संरेखण को ठीक करने, सुरंग मार्ग के साथ भूगर्भिक स्थितियों का मूल्यांकन करने, भू-तकनीकी विश्लेषण की आवश्यकता और रॉक सपोर्ट तथा कमजोर क्षेत्रों के उपचार के प्रस्तावों के लिए आवश्यक भूवैज्ञानिक जांच हेतू विशिष्ट दिशानिर्देश प्रदान करता है। इसमें जांच के विभिन्न चरणों में किए जाने वाले सतही और सतह जे नीचे दोनों प्रकार के अन्वेषण भी शामिल हैं। चर्चा के बाद, प्रस्तावित प्रारूप को संबंधित संगठनों को आगे की टिप्पणियों के लिए भेजा गया । इस बैठक में के.ज.आ., समिति के सदस्यों ने भाग लिया।

राजस्थान और सरहिंद फीडर के रिलाइनिंग के कार्यों की स्थिति की समीक्षा

राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रिलाइनिंग के संबंध में कार्यों की स्थिति की समीक्षा करने के लिए सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. की अध्यक्षता में विशेषज्ञ परियोजना समीक्षा समिति की तीसरी बैठक 02.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई । समिति के सभी सदस्य जिसमें के.ज.आ., पंजाब और राजस्थान सरकार, सीडब्ल्यूपीआरएस, सीएसएमआरएस और आईआईटी दिल्ली के अधिकारी शामिल थे, बैठक में उपस्थित थे।

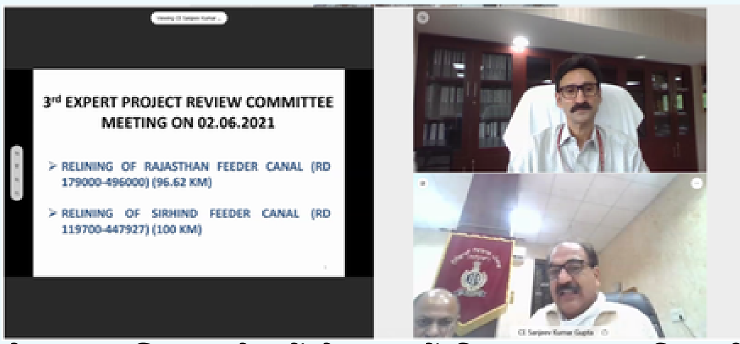

सतलुज और ब्यास नदियों के संगम के अनुप्रवाह में निर्मित हरिके हेडवर्क्स के अपस्ट्रीम में राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की शुरुवात होती है। 5439 क्यूसेक क्षमता वाला सरहिंद फीडर पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों में काम करता है। राजस्थान को पानी उपलब्ध कराने के लिए पीछे के हिस्से पर इसकी डिजाइन क्षमता 1668 क्यूसेक है। सरहिंद फीडर सिंचाई के अलावा पंजाब और राजस्थान राज्यों के कुछ क्षेत्रों में पीने का पानी उपलब्ध कराता है। 18500 क्यूसेक क्षमता वाला राजस्थान फीडर विशेष रूप से इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो कि राजस्थान क्षेत्र में स्थित कमान के लिए कार्य करती है ,को पानी उपलब्ध कराने के लिए है। राजस्थान फीडर सिंचाई के अलावा राजस्थान राज्य को पेयजल भी उपलब्ध कराता है। राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर एक ही तटबंध साझा करते हैं और समानांतर चलते हैं। इन दो नहरों को 50 के दशक के अंत में निर्माण के लिए लिया गया था और 60 के दशक के मध्य में पूरा किया गया था। दोनों फीडरों का निर्माण ईंट की टाइलों के साथ पंक्तिबद्ध चैनलों के रूप में किया गया था। फिर भी, रिसाव होता रहा जो हाल के दिनों में अस्तर में क्षति के कारण बढ़ गया है।

रिलाइनिंग परियोजनाओं को अप्रैल, 2016 में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा 1305.267 करोड़ रुपये (कार्य- 1210.417 करोड़ रुपये और अनुमानित- 94.85 करोड़ रुपये) और 671.478 करोड़ रुपये (कार्य- 623.08 करोड़ रुपये और स्थापना- रुपये 48.40 करोड़) के लिए क्रमश: 2015 के मूल्य स्तर पर निवेश मंजूरी दी गई है। इसके अलावा 2018 में, केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए सरहिंद फीडर (एसएफ) और राजस्थान फीडर (आरएफ) के लिए क्रमश: 205.758 करोड़ और 620.41 करोड़ रुपये के लिए कैबिनेट की मंजूरी दी गई थी। उपरोक्त के अलावा, 2013-14 के दौरान सरहिंद फीडर के लिए 50.00 करोड़ रुपये और 2010-11 के दौरान राजस्थान फीडर के लिए 105.84 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता प्रदान किए गए।

तल पर एचडीपीई परत बिछाना

विवरण	सरहिंद फीडर	राजस्थान फीडर
कुल सीसीए (लाख हेक्टेयर)	621000	1963000
रिलाइनिंग के बाद अनुमानित जल बचत(क्यूसेक)	256	560
पानी की बचत के कारण स्थिरीकरण/बेहतर सिंचाई (हेक्टेयर)	69096 (पंजाब और राजस्थान)	98739 (राजस्थान)
पूर्ण किया गया रिलाइनिंग कार्य (लगभग किमी)	44	23
मई, 2021 तक कुल व्यय (करोड़ रुपये)	221.13	187.89

आईडब्ल्यूआरएस और आईआईटी, रुड़की द्वारा आयोजित जल स्रोत स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन

श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. को 18-20 जून, 2021 के दौरान आईआईटी रुड़की और इंडियन वाटर रिसोर्स सोसाइटी (आईडब्ल्यूआरएस) द्वारा आयोजित जल स्रोत स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन के दौरान मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वक्ताओं ने जल आपूर्ति और मांग प्रबंधन, जल स्रोत स्थिरता, टिकाऊ सिंचाई प्रबंधन, जल शासन, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव आदि जैसे विभिन्न पहलुओं पर बात की।

श्री के. वोहरा ने 18.06.2021 को कार्यक्रम के दौरान "सिंचाई के बुनियादी ढांचे में आधुनिकीकरण की आवश्यकता" शीर्षक से एक प्रस्तुति दी।

जैसा कि के.ज.आ. और जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग द्वारा किए गए विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि भारत में वृहत और मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं से संबंधित कम जल उपयोग दक्षता, कम जल उत्पादकता, न्यायसंगत और विश्वसनीय सेवा वितरण की कमी आदि है, प्रस्तुतिकरण उपरोक्त मुद्दों पर केंद्रित था। इस

प्रस्तुतिकरण ने सिंचाई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला तथा भारत सरकार और कुछ राज्यों द्वारा सिंचाई आधुनिकीकरण की दिशा में जैसे कि पाइप वितरण नेटवर्क का उपयोग, नहर स्वचालन, सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार पुनर्वास और आधुनिकीकरण (ईआरएम), सूक्ष्म सिंचाई, आदि पहले से शुरू किए गए विभिन्न कार्यों को भी प्रदर्शित किया। प्रस्तुति में भारत में एमएमआई परियोजनाओं के आधुनिकीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के तकनीकी सहयोग से के.ज.आ. द्वारा नई पहल “सिंचाई आधुनिकीकरण कार्यक्रम के लिए सहायता (एसआईएमपी)” के बारे में भी बात की गई।

सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. को भारतीय जल संसाधन सोसायटी (IWRS) पुरस्कार

भारतीय जल संसाधन सोसायटी (IWRS) की स्थापना 1980 में सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत सोसायटी के रूप में की गई थी। भारतीय जल संसाधन सोसायटी (IWRS) का पंजीकृत कार्यालय जल संसाधन विकास प्रशिक्षण केंद्र, आई आई टी (I.I.T), रुड़की में स्थित है। भारतीय जल संसाधन सोसायटी में लगभग 7408 वैयक्तिक; 335 शोध कर्ता और 48 संस्थागत सदस्य हैं। भारतीय जल संसाधन सोसायटी का मुख्य उद्देश्य जल संसाधन विकास और प्रबंधन के तकनीकी और नीतिगत पहलुओं में ज्ञान की उन्नति है। IWRS पानी के मुद्दों से संबंधित लोगों के बीच स्वतंत्र और स्पष्ट चर्चा के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।

सोसायटी हर साल इस क्षेत्र के प्रख्यात वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को पुरस्कार प्रदान करता है। श्री कुशविंदर वोहरा, सदस्य (डब्ल्यूपी एंड पी), के.ज.आ. को भारतीय जल संसाधन सोसायटी द्वारा भारत में जल क्षेत्र के विकास में उनके योगदान के लिए "प्रतिष्ठित जल संसाधन इंजीनियर पुरस्कार- 2019" के लिए चुना गया। उन्होंने प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना

Eminent Water Resources Engineer Award- 2019

Sh. Kushvinder Vohra currently holds the post of Member (WP&P), Higher Administrative Grade (HAG) of (Gr. 'A') in the Central Water Engineering Service, Central Water Commission. He completed Civil Engineering in 1985 from Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala and also has an L.L.B degree from the Delhi University. In his professional career he has been instrumental in numerous important areas like formulation, approval and implementation of schemes such as Pradhan Mantri Krishi Sinchaee Yojana (PMKSY), Special Package for Irrigation Projects in Maharashtra Rajasthan, Feeder – Sirhind Feeder and also 99 Major / Medium Irrigation (MMI) projects were prioritized in the country for completion in phases.

He also played a major role in water conflict resolution between Telengana and Andhra Pradesh on the usage of Krishna River water. He is actively involved in the Inter-linking of Rivers programme in preparation of PFR, DPRs of ILR Project, and building consensus amongst concerned States. Numerous papers presented at National / International Forums and published in National / International Journals.

(पीएमकेएसवाई), महाराष्ट्र में सिंचाई परियोजनाओं के लिए विशेष पैकेज, राजस्थान फीडर- सरहिंद फीडर और 99 प्रमुख/मध्यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के प्राथमिकीकरण के लिए योजनाओं के निर्माण, अनुमोदन और कार्यान्वयन जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में योगदान दिया है। यह पुरस्कार 18.06.2021 को आयोजित जल स्रोत स्थिरता पर अंतर्राष्ट्रीय ई-सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में प्रस्तुत किया गया था।

"ब्रह्मपुत्र नदी के बाढ़ और कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" योजना पर टीएसी-बीबी

ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी-बीबी) की तकनीकी सलाहकार समिति के सदस्यों ने 15.06.2021 को शाम 4.00 बजे से "बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से माजुली द्वीप की सुरक्षा" योजना के कार्य स्थलों का वर्चुअल दौरा किया।

टीएसी-बीबी "ढोला-हातीघुली चरण-V में दिबांग और लोहित नदियों की उनके मूल मार्ग में बहाली"

तकनीकी सलाहकार समिति, ब्रह्मपुत्र बोर्ड (टीएसी-बीबी) ने 16.06.2021 को सुबह 9:30 बजे से "दिबांग और लोहित नदियों को उनके मूल मार्ग पर बहाल करने के लिए चरण-V में - दिबांग नदी के स्पिल चैनल पर बने टाई बांध को पूर्ण तटबंध में रूपांतरित करने और चरण-V भाग –ए -बहबरी में नए तटबंध का निर्माण परियोजना स्थल का एक आभासी दौरा किया । टीएसी-बीबी ने चल रहे कार्यों की प्रगति का जायजा लिया और कार्य के निष्पादन के दौरान आने वाली तकनीकी चुनौतियों पर उपयुक्त उपाय सुझाए।

उपमुख्यमंत्री, दिल्ली की अध्यक्षता में बाढ़ नियंत्रण उपायों की समीक्षा के लिए शीर्ष समिति की बैठक

उपमुख्यमंत्री, दिल्ली की अध्यक्षता में मानसून-2021 की शुरुआत से पहले बाढ़ नियंत्रण उपायों और तैयारियों की समीक्षा के लिए शीर्ष समिति की बैठक 23.06.2021 को आयोजित की गई थी और इसमें सदस्य (आरएम), के.ज.आ. और निदेशक एफएम- I, के.ज.आ. ने भाग लिया।

माजुली द्वीप को बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से बचाने के लिए निगरानी समिति का चौथा दौरा

"बाढ़ और ब्रह्मपुत्र नदी के कटाव से माजुली द्वीप का संरक्षण" योजना के लिए निगरानी समिति के सदस्यों ने 18.06.2021 और 06.07.2021 को किनारों के प्रत्यावर्तन के छह विस्तार क्षेत्र, तीन स्पर साइट, सीसी ब्लॉक कास्टिंग और आरसीसी का वर्चुअल दौरा किया। समिति की अध्यक्षता सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ., नई दिल्ली ने की थी। निगरानी समिति के सदस्यों को वस्तुतः विभिन्न कार्य स्थानों पर ले जाया गया जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी स्थापित की जा सकती थी और निष्पादित कार्यों को तस्वीरों, वीडियो क्लिप और उन साइटों से लाइव कवरेज की मदद से दिखाया गया।

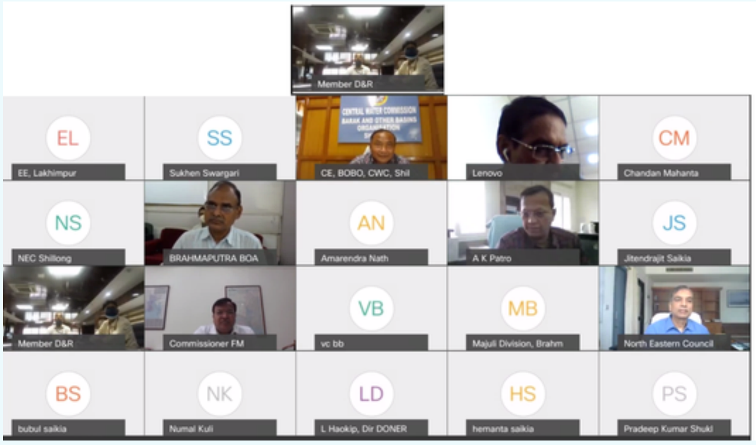

सूमोईमारी में तट आवरण कार्य

आरसीसी प्रोक्युपाइन वर्क

जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग के लिए आपदा प्रबंधन योजना और डीएमपी पर प्रस्तुति

एनडीएमए ने 23.06.2021 को वर्चुअल मोड में आयोजित एक बैठक में जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग की आपदा प्रबंधन योजना (डीएमपी) की समीक्षा की। निदेशक (एफएफएम) ने विभाग के डीएमपी पर एक प्रस्तुति दी, जिसे बांध विफलताओं के कारण बाढ़ जैसी स्थितियों/ प्राकृतिक आपदाओं आदि और बाढ़ पूर्वानुमान से संबंधित मामलों के लिए एक नोडल प्राधिकरण के रूप में कार्य करने के लिए अनिवार्य किया गया है। बैठक में श्री. कमल किशोर, सदस्य, एनडीएमए, लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, सदस्य, एनडीएमए, श्री. राजेंद्र सिंह, सदस्य, एनडीएमए श्री. कृष्णा एस वत्स, सदस्य, एनडीएमए, डॉ वी थिरुप्पुगज़, अतिरिक्त सचिव, सदस्य (आरएम), के.ज.आ., आयुक्त (एफएम) और एसजेसी (एफएम), जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग उपस्थित थे। एनडीएमए सदस्यों ने विभाग के व्यापक डीएमपी दस्तावेज़ की सराहना की और योजना में शामिल करने के लिए कुछ अतिरिक्त

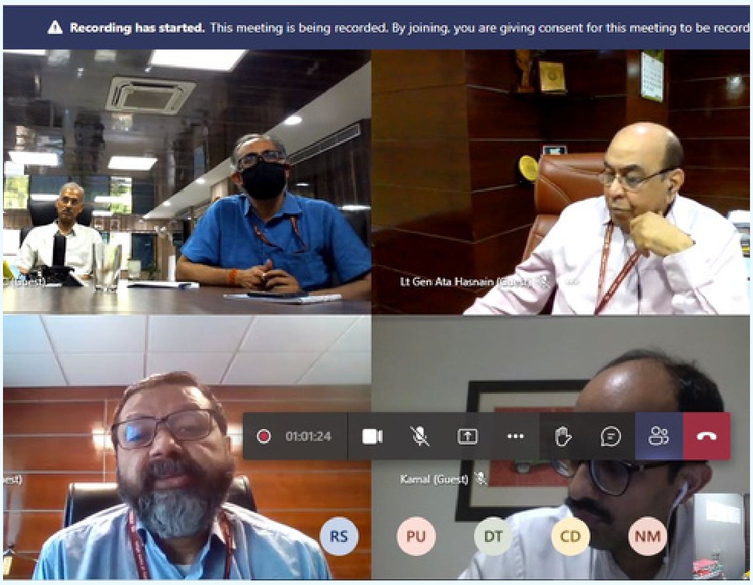

सुविधाओं का सुझाव दिया।

भारत-ऑस्ट्रेलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक- सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना के लिए सिंचाई दक्षता कार्यक्षेत्र अध्ययन

07.06.2021 को भारत-ऑस्ट्रेलियाई तकनीकी अधिकारियों की वर्चुअल बैठक हुई। बैठक की सह-अध्यक्षता भारतीय पक्ष से श्री पी. दोर्जे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. ने और श्री एडम सिनकॉक, निदेशक, इन्टरनेशनल एंगेजमेंट एंड अर्बन वाटर सेक्शन (आईईयूडब्ल्यू), वाटर डिविजन ने ऑस्ट्रेलियाई पक्ष से की थी। बैठक में इरिगेशन ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड (आईएएल) के अधिकारियों ने भी भाग लिया, जिन्हें ऑस्ट्रेलियाई पक्ष द्वारा 'स्कोप आफ स्टडी' सौंपा गया है । अंतिम बैठक 10.3.2021 को हुई थी।

बैठक का एजेंडा सुवर्णरेखा सिंचाई परियोजना (ओडिशा) को पेश करना था, जिसे भारत-ऑस्ट्रेलिया समझौता ज्ञापन के तहत सिंचाई दक्षता पायलट परियोजना के लिए लिया गया है। के.ज.आ. और डब्ल्यूआरडी, ओडिशा सरकार के अधिकारी ने सुवर्णरेखा परियोजना के तहत मां किचकेश्वरी पानीपंचायत कमान पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति दी जिसमें पानी के स्रोत, भूमि की स्थिति, किसानों की भूमि, मिट्टी के प्रकार, भूजल की स्थिति, वर्षा, वर्तमान सिंचाई बुनियादी ढांचे, सीएडी गतिविधियों के

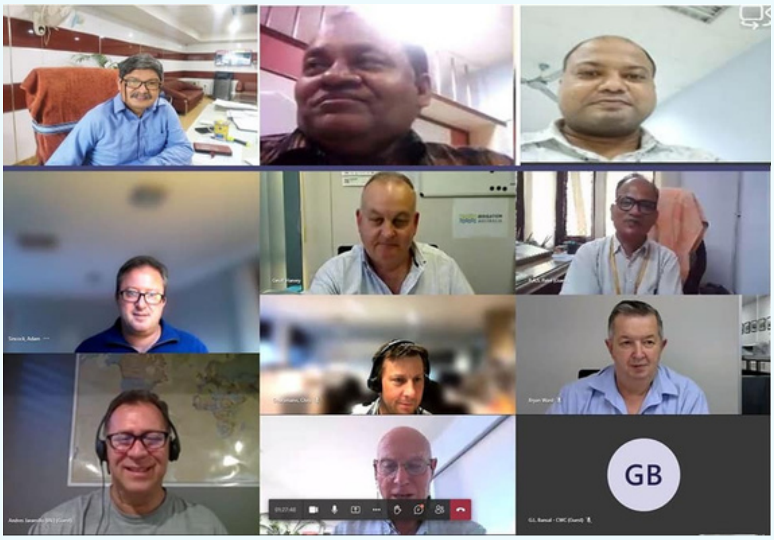

कार्यान्वयन वर्तमान सिंचाई पद्धतियां, वर्तमान कृषि उत्पाद, मौजूदा सिंचाई अवसंरचना आदि जैसे विभिन्न पहलू शामिल थे। । पायलट परियोजना के तहत 'स्कोप आफ स्टडी' को बढ़ाने के लिए आईएएल द्वारा मांगी जाने वाली आवश्यक जानकारी के संबंध में भी चर्चा की गई और उन्हें वह जानकारी प्रदान की गई।

राष्ट्रीय जल मिशन- बेसलाइन स्टडी - वालामतरी, हैदराबाद के साथ बैठक

रल्लापाडु मध्यम सिंचाई परियोजना (आंध्र प्रदेश) के बेसलाइन स्टडी के लिए वालमतरी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट के मसौदे पर चर्चा करने के लिए 23.06.2021 को वर्चुअल मोड के माध्यम से आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और जल और भूमि प्रबंधन प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान (वालमतरी), हैदराबाद के अधिकारियों के साथ श्री पी. दोरजे ग्याम्बा, मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ), के.ज.आ. की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी।

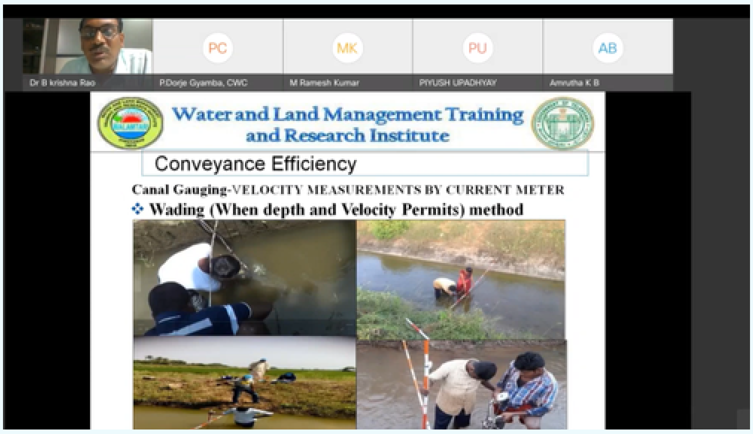

राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा मिशन के 5 लक्ष्यों में से एक जिसका उद्देश्य जल उपयोग दक्षता को 20% तक बढ़ाना है के अनुरूप देश में वृहत/ मध्यम सिंचाई परियोजनाओं में जल उपयोग दक्षता का आकलन करने के लिए बेसलाइन स्टडी किया गया है। मुख्य अभियंता (पीओएमआईओ) इन अध्ययनों को संचालित करने के लिए गठित कोर ग्रुप के सदस्यों में से एक है और "सिंचाई परियोजनाओं की जल उपयोग दक्षता की गणना" के लिए के.ज.आ. के दिशानिर्देशों के आलोक में अध्ययन के दौरान रिपोर्ट की तकनीकी जांच के लिए जिम्मेदार है।

ड्रिप

ड्रिप चरण II और चरण III की भागीदार एजेंसियों की प्रगति की समीक्षा के लिए बैठक

ड्रिप चरण II की एजेंसियों की प्रगति की समीक्षा करने के लिए संयुक्त बैठकें राजस्थान डब्ल्यूआरडी, यूजेवीएनएल, मणिपुर डब्ल्यूआरडी, मेघालय पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड , केरल डब्ल्यूआरडी, केएसईबी और गुजरात एनडब्ल्यूआर, डब्ल्यूएस & केडी के साथ क्रमश:11 जून, 15 जून,16 जून, 18 जून, 23 जून, 25 जून और 29 जून, 2021 को आयोजित की गईं। साझेदार एजेंसियों द्वारा हासिल की गई प्रगति और डीईए की तैयारी के मानदंडों को पूरा करने के लिए कार्य योजना पर विचार-विमर्श किया गया, जिसके लिए विश्व बैंक के साथ ऋण पर हस्ताक्षर करने के लिए लागत अनुमान के न्यूनतम 30% के लिए सिविल अनुबंध देने की आवश्यकता है। बैठकों में

मंत्रालय, सीपीएमयू, विश्व बैंक के अधिकारी और राज्य के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

देश में बाढ़ की स्थिति

1 मई से 30 जून 2021 की अवधि के दौरान, 852 बाढ़ पूर्वानुमान (579 स्तर और 273 अंतर्वाह) जारी किए गए, जिनमें से 777 (563 स्तर और 214 अंतर्वाह) पूर्वानुमान 91.19% की सटीकता की सीमा के भीतर सही थे। जून महीने में सेंट्रल फ्लड कंट्रोल रूम से कोई रेड बुलेटिन (चरम बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी नहीं किया गया और 97 ऑरेंज बुलेटिन (गंभीर बाढ़ की स्थिति के लिए) जारी किए गए ।

बाढ़ की श्रेणी	कितने स्टेशनों द्वारा रिपोर्ट की गई	राज्य/संघ
चरम बाढ़ की स्थिति (एफएफ स्टेशन)	0	लागू नहीं
चरम बाढ़ की स्थिति (बाढ़ निगरानी स्टेशन)	1	तमिलनाडु
गंभीर बाढ़ की स्थिति (एफएफ स्टेशन)	16	असम, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड
सामान्य बाढ़ की स्थिति से ऊपर	37	असम, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल
सीमा से अधिक अंतर्वाह वाले जलाशय	28	कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तमिलनाडु

एनएचपी के तहत के.ज.आ. की गतिविधियां और प्रगति

क्र.सं.	विषय	स्थिति
1	जल-मौसम संबंधी आंकड़ों को मापने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकियों की खरीद	
क	नई एडीसीपी	29 एडीसीपी की खरीद के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है
ख	वेलोसिटी राडार	13 वेलोसिटी राडार सिस्टम की खरीद के लिए निविदा प्रक्रियाधीन है
2	हाइड्रो ग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करके जलाशय अवसादन अध्ययन	चरण-I (32 जलाशयों) के लिए जनवरी, 2021 में कार्य प्रदान किया गया।10 जलाशयों का प्रारंभिक सर्वेक्षण और 6 जलाशयों का हाइड्रो-ग्राफिक सर्वेक्षण का कार्य पूरा कर लिया गया है।
3	पूर्व बाढ़ चेतावनी प्रणाली सहित गंगा बेसिन में बाढ़ पूर्वानुमान	प्रस्ताव मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। मंजूरी के बाद काम दिया जाएगा
4	"गंगा बेसिन के एकीकृत जलाशय संचालन प्रणाली के लिए रियल टाइम अनुमान लगाने के लिए-डीएसएस के विकास" हेतू परामर्श सेवाएं	प्रस्ताव मंत्रालय को अनुमोदन के लिए भेजा गया है। अनुमोदन के बाद कार्य प्रदान किया जाएगा
5	बिहार राज्य में फरक्का बैराज के कारण गंगा नदी और उसकी सहायक नदियों में बाढ़ और गाद के मुद्दे पर अध्ययन	मार्च, 2021 में परामर्श सेवाएं प्रदान की गई। सलाहकार द्वारा इनसेपशन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है
6	जल गुणवत्ता परीक्षण सामान/उपकरण और संबंधित सेवाओं की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमीशनिंग	जल गुणवत्ता परीक्षण उपकरण 3 जीसीएमएस और 4 आईसीपी-एमएस के.ज.आ. की जल गुणवत्ता प्रयोगशालाओं को वितरित किए गए हैं
7	नर्मदा बेसिन में रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली	अगस्त, 2020 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्य प्रगति पर है
8	अरुणाचल प्रदेश में रियल टाइम डेटा अधिग्रहण प्रणाली	नवंबर,2020 में अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। कार्य प्रगति पर है।

एनएचपी के तहत हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन

जलाशय अवसादन एक महत्वपूर्ण चिंता का विषय है और जल क्षेत्र में अत्यधिक महत्व के विषयों में से एक है। के.ज.आ. ने राष्ट्रीय महत्व के लगभग 191 जलाशयों का अवसादन सर्वेक्षण करने की योजना बनाई है। अध्ययन के लिए राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना(एनएचपी) के परियोजना कार्यान्वयन योजना (पीआईपी) के अंतर्गत 30 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है।

अध्ययन का पहला चरण फरवरी 2021 में शुरू किया जा चुका है जिसमें राजस्थान, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और बिहार राज्यों के 32 जलाशयों को लिया गया है। राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी) चरण- I के तहत भारत में 32 जलाशयों के हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण का उपयोग करते हुए जलाशय अवसादन अध्ययन की मासिक प्रगति समीक्षा के लिए तीसरी बैठक 09.06.2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित की गई थी। मई 2021 की मासिक प्रगति रिपोर्ट मेसर्स टीवीआईपीएल प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत की गई और मुख्य अभियंता, ईएमओ, के.ज.आ. की अध्यक्षता में समिति के सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई।

एनडब्ल्यूडीए के साथ डीवीजी और डीईजी लिंक के संबंध में वर्चुअल बैठक

तटबंध (एनडब्ल्यूएंडएस), गेट्स (एनडब्ल्यूएंडएस), बीसीडी (एनडब्ल्यूएंडएस) और एचसीडी (एनडब्ल्यूएंडएस) के डिजाइन (एनडब्ल्यूएंडएस) यूनिट अधिकारियों ने 29.06.2021 को एनडब्ल्यूडीए अधिकारियों के साथ एक आभासी बैठक में भाग लिया। यह बैठक दमनगंगा-वैतरणा-गोदावरी (डीवीजी) और दमनगंगा-एकदारे-गोदावरी लिंक (डीईजी) के अंतर्राज्यीय नदी लिंक के लिए डीपीआर डिजाइन के संबंध में प्रासंगिक परीक्षण / फील्ड डेटा प्रदान करने के लिए आयोजित की गई थी। एनडबल्यूडीए की ओर से बैठक में महानिदेशक, मुख्य अभियंता मुख्यालय, मुख्य अभियंता, हैदराबाद और अधीक्षक अभियंता-I, नई दिल्ली और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

30.06.2021 तक योजनाओं/घटकों की वित्तीय प्रगति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रमांक	योजना/घटक का नाम	बजट अनुमान (2021-22)	व्यय(जून, 21 तक)	व्यय(% में)
1	जल संसाधन सूचना प्रणाली का विकास (डीडब्ल्यूआरआईएस)	166.100	20.262	12.20
2	जल संसाधन विकास योजनाओं (आईडब्ल्यूआरडी) की जांच	12.000	1.709	14.25
3	बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम (एफएमबीएपी)	27.408	1.868	6.84
4	अवसंरचना विकास (आईडी)योजनाएं	4.500	1.228	27.29
5	बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी)	25.000	1.850	7.4
6	राष्ट्रीय जल विज्ञान परियोजना (एनएचपी)	23.905	1.504	6.29

जल क्षेत्र-समाचार

- पानी के लिए बंगाल को 7000 करोड़ (नवभारत टाईम्स, 02.06.2021)
- राजस्थान ने नहीं छोड़ा पानी, चंबल नदी में जलस्तर सिर्फ एक फीट बचा, 40 किमी का फेरा बचाने पैदल पार कर रहे नदी (राष्ट्रीय सहारा, 02.06.2021)
- चीन ने ब्रह्मपुत्र और सतलुज नदी के बहाव का डाटा देना शुरू किया (अमर उजाला, 02.06.2021)
- यमुना निगरानी समिति के पुनर्गठन की याचिका एनजीटी से खारिज (जनसत्ता, 03.06.2021)
- गंगा नदी में बहते शवों को हटाने के निर्देश देने का अनुरोध (जनसत्ता, 03.06.2021)
- केरल पहुंचा मानसून, रायपुर—दुर्ग में अंधड़ के साथ तेज बारिश (राजस्थान पत्रिका, 04.06.2021)
- सीएम ने कहा — लखवाड़ परियोजना को मिले कैबिनेट कमेटी की अनुमति (दैनिक भास्कर, 07.06.2021)
- गंगा जल में कोरोना की मौजूदगी पर केंद्र ने शुरू किया अध्ययन (अमर उजाला, 08.06.2021)
- गंगा में मिले हरे शैवाल के लिए जांच के लिए टीम गठित (राजस्थान पत्रिका, 09.06.2021)
- भारत को मिलेगा सिंधु जल संधि का पानी : केंद्रीय मंत्री (दैनिक जागरण, 11.06.2021)
- इंदिरा गांधी नहर में अब मटमैले की जगह प्रवाहित हो रहा हरा पानी (राजस्थान पत्रिका, 11.06.2021)
- मानसून एक्सप्रेस ने पकड़ी रफ्तार, मध्य प्रदेश में 8 दिन पहले दस्तक (राजस्थान पत्रिका, 11.06.2021)
- दावा : ग्लेशियर पिघलने से 2050 के बाद घटने लगेगा हिमालयी नदियों का जल (हिन्दुस्तान, 12.06.2021)
- जल जीवन मिशन : उत्तर प्रदेश को 10,870 करोड़ का केंद्रीय अनुदान (राष्ट्रीय सहारा, 13.06.2021)
- अमित शाह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों का लिया जायजा, दिए निर्देश (दैनिक जागरण, 16.06.2021)
- 'कैच द रेन' अभियान से जुड़ें... (पंजाब केसरी, 16.06.2021)
- मौसम भविष्यवाणी संबंधी मोबाइल एप उमंग, रैन अलार्म, दामिनी का अधिकतम प्रचार हो : अमित शाह (राजस्थान पत्रिका, 16.06.2021)
- बनारस : गंगा में रोज गिर रहा 7 करोड़ लीटर सीवर का पानी, अफसर बोले — जल्द रोकेंगे (दैनिक भास्कर, 19.06.2021)
- भाखड़ा नांगल से राजस्थान को मिलेगा 2700 क्यूसेक अतिरिक्त पानी : शेखावत (राजस्थान पत्रिका, 19.06.2021)
- गंगा व सहायक नदियों के पुनरुद्धार के लिए समिति का गठन (जनसत्ता, 19.06.2021)
- जल्द स्थापित होगा राष्ट्रीय जल उपयोग दक्षता ब्यूरो (राष्ट्रीय सहारा, 22.06.2021)
- लक्षद्वीप : 14 साल में ज्यादातर द्वीपों के डूबने का खतरा (जनसत्ता, 29.06.2021)

डेटा कॉर्नर- 1955-2015 की अवधि के दौरान वर्षा के तुलनात्मक आंकड़े

क्रमांक	बेसिन	जल वर्ष(1955-1984) में औसत वर्षा		जलवर्ष(1965-1984) में औसत वर्षा		जलवर्ष(1985-2015) में औसत वर्षा	
		मिमी	बीसीएम	मिमी	बीसीएम	मिमी	बीसीएम
1	सिंधु (भारत के भीतर)	762	303	752	299	895	356
2	गंगा- ब्रह्मपुत्र-मेघना						
	क) गंगा	1069	978	1035	947	1007	914
	क) ब्रह्मपुत्र	2589	551	2635	561	2330	495
	क) बराक और अन्य	2462	126	2593	133	2625	134
3	गोदावरी	1122	365	1062	346	1117	365
4	कृष्णा	842	225	797	213	841	226
5	कावेरी	957	82	948	81	949	81
6	सुवर्णरेखा	1412	40	1408	40	1427	40
7	ब्राह्मणी-बैतरनी	1407	80	1369	78	1456	83
8	महानदी	1311	200	1237	189	1317	200
9	पेन्नार	684	38	675	38	716	40
10	माही	840	36	839	36	811	35
11	साबरमती	726	25	711	24	727	25
12	नर्मदा	1133	117	1104	114	1045	108
13	तापी	876	61	838	58	839	59
14	तापी से ताद्री तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	2664	161	2548	154	2661	161
15	ताद्री से कन्याकुमारी तक पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	3059	166	2929	159	2773	151
16	महानदी और पेन्नार के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	1081	91	1035	88	1144	97
17	पेन्नार और कन्याकुमारी के बीच पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ	928	95	938	96	960	98
18	लूनी सहित कच्छ और सौराष्ट्र की पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ	482	100	465	96	479	100
19	राजस्थान में अंतर्देशीय जल निकासी का क्षेत्र	317	51	305	49	302	49
20	म्यांमार (बर्मा) और बांग्लादेश में बहने वाली छोटी नदियाँ	1680	57	1733	58	1812	61
	कुल	1123	3945	1096	3853	1105	3880

स्रोत: अंतरिक्ष इनपुट का उपयोग कर बेसिनों में पानी की उपलब्धता का पुनर्मूल्यांकन, के.ज.आ. और इसरो, 2019

जून-2021 के दौरान एनडब्ल्यूए, पुणे द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रमांक	प्रशिक्षण कार्यक्रम का नाम	अवधि/दिनांक	प्रशिक्षुओं की संख्या	श्रेणी
1.	एशियाई क्षेत्र के लिए हाइड्रोलिक्स,हाइड्रोलॉजिकल साइंसेज और हाइड्रोमेटोरोलॉजी में उन्नत विषयों में चौथा अंतर्राष्ट्रीय दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम (प्रगति में)	31मई 2021-16 जुलाई 2021	91	आरटीसी-डब्ल्यूएमओ
2.	स्कूली शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम -V	01-03 जून 2021	187	जन जागरूकता
3	स्कूली शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम -VI	02-04 जून 2021	199	जन जागरूकता
4	स्कूली शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम -VII	07-09 जून 2021	183	जन जागरूकता
5	स्कूली शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम -VIII	08-10 जून 2021	178	जन जागरूकता
6	स्कूल शिक्षकों के लिए भारत के जल संसाधन क्षेत्र पर दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम-IX	09-11 जून 2021	162	जन जागरूकता
7	जल विज्ञान परियोजना पर दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण	07-18 जून 2021	92	तकनीकी
8	ई-गवर्नेंस टूल्स पर वेबिनार श्रृंखला के माध्यम से उद्देश्य उन्मुख प्रशिक्षण	07-11 जून 2021	291	तकनीकी
9	आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, बेंगलुरू के साथ लोक प्रशासन में व्यक्तिगत उत्कृष्टता के लिए क्षमता निर्माण पर प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑन-लाइन मोड (बैच-I)	22-25 जून 2021	20	संकाय विकास
10	वेबिनार 1: भारत के जल क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग: जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय की भूमिका	07.06.2021	188	नीति
11	वेबिनार 2: अंतर्राष्ट्रीय जल कानून के विकास का इतिहास; सीमा-पार घाटियों में जल आवंटन; हेलसिंकी नियम (1966), बर्लिन नियम (2004)	14.06.2021	179	नीति
12	वेबिनार 3: अंतर्राष्ट्रीय जल कानून: संयुक्त राष्ट्र जलमार्ग सम्मेलन 1997 और अन्य उपकरण	21.06.2021	164	नीति
13	वेबिनार 4: सिंधु जल संधि –सर्वाइविंग द आइस	28.06.2021	168	नीति

उच्च अध्ययन

आईआईएससी बंगलौर, आईआईटी रुड़की और अन्ना विश्वविद्यालय, चेन्नई में सत्र 2021-23 के लिए 2 वर्षीय एम.टेक कोर्स करने के लिए नौ के.ज.आ. अधिकारियों को प्रायोजित किया गया है।

गैलरी

डॉ आर के गुप्ता, सदस्य (डी एंड आर), के.ज.आ. आईसीआईडी द्वारा इसके 72वां स्थापना दिवस पर 24.06.2021 को आयोजित वेबिनार में विषय कठिन परिस्थितियों में कृषि जल प्रबंधन की स्थिरता पर प्रस्तुति दी गई

फिश लैडर- पोलावरम सिंचाई परियोजना

नर्मदा नदी की सहायक नदी हालोन नदी पर 31 मीटर ऊंचा, 1000 मीटर लंबा कम्पोजीट ग्रैविटी हालोन बांध। यह लगभग 13000 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्रदान करता है। इसे के.ज.आ. द्वारा डिजाइन किया गया था और पिछले साल कमीशन किया गया

जलाशय निगरानी

के.ज.आ. देश के 130 जलाशयों की लाइव भंडारण स्थिति की निगरानी करता है और प्रत्येक गुरुवार को साप्ताहिक जलाशय बुलेटिन जारी करता है। उपरोक्त में से 44 जलाशयों में जल विद्युत लाभ के साथ 60 मेगावाट से अधिक की स्थापित क्षमता है। इन 130 जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता 174.233 बीसीएम है जो देश में सृजित 257.812 बीसीएम की सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 67.58% है।

24.06.2021 के बुलेटिन के अनुसार, इन जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण 54.37 बीसीएम था जो इन जलाशयों की कुल सजीव भंडारण क्षमता का लगभग 31% है। हालांकि, पिछले साल इसी अवधि के लिए इन जलाशयों में उपलब्ध सजीव भंडारण 57.494 बीसीएम था और पिछले दस वर्षों के सजीव भंडारण का औसत 38.003 बीसीएम था। इस प्रकार, 130 जलाशयों में उपलब्ध संग्रहण पिछले वर्ष की इसी अवधि के लाइव संग्रहण का 95 प्रतिशत और दस वर्ष के औसत संग्रहण का 143% है।

पिछले दो वर्षों में, के.ज.आ. ने अपने निगरानी नेटवर्क के तहत लगभग 39 अतिरिक्त जलाशय जोड़े हैं और निगरानी की जा रही सजीव भंडारण क्षमता को लगभग 12.24 बीसीएम बढ़ाया गया है।

इतिहास

बांध और जलाशय सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाने और बाढ़ और सूखे की अनिश्चितता से पीड़ित दुनिया की एक बड़ी आबादी के दुखों को कम करने के लिए नदी के पानी के उपयोग में दोहरी भूमिका निभा रहे हैं। घरेलू और औद्योगिक उपयोग के लिए पानी, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, जल विद्युत, नेविगेशन और मनोरंजन जैसी बुनियादी मानवीय जरूरतों को पूरा करने में बांध और जलाशय महत्वपूर्ण योगदान देते हैं

कृष्णा राज सागर (केआरएस) बांध मांड्या जिले के श्रीरंगपटना तालुके में कन्नमबाडी गांव के पास कावेरी नदी पर स्थित है, जो सुरकी गारे के साथ पत्थर की चिनाई के माध्यम से निर्मित एक प्रकार का ग्रेविटी बांध है। केआरएस बांध का नाम मैसूर के महाराजा कृष्ण राजा वोडेयार चतुर्थ के नाम पर रखा गया है, जिनके शासनकाल में इस बांध का निर्माण हुआ था। प्रसिद्ध इंजीनियर और भारत रत्न से सम्मानित श्री एम. विश्वेश्वरैया इस प्रभावशाली बांध के डिजाइन और निर्माण से जुड़े थे।

बांध की आधारशिला अक्टूबर 1911 में रखी गई थी और बांध का निर्माण वर्ष 1932 में पूरा हुआ था। बांध कावेरी नदी के हेमवती और लक्ष्मणतीर्थ के संगम के नीचे स्थित है और ऐतिहासिक शहर श्रीरंगपटना के ऊपर की ओर लगभग 14 किमी और मैसूर शहर से 19 किमी है। बांध की लंबाई लगभग 2621 मीटर है और सबसे निचली नींव से बांध की अधिकतम ऊंचाई 42.672 मीटर है। बांध द्वारा निर्मित जलाशय में 1.400 बीसीएम की सकल भंडारण क्षमता और 1.276 बीसीएम की सक्रिय भंडारण क्षमता है। जलाशय के दाहिनी ओर 2 नहरें हैं और इसके बाईं ओर एक नहर है जिसका नाम विश्वेश्वरैया नहर है।

कृष्णा राज सागर (KRS) डैम

केआरएस बांध भी मांड्या और मैसूर के लिए पेयजल और सिंचाई के पानी के मुख्य स्रोतों में से एक है। इसके साथ ही इसका प्रमुख उद्देश्य शिवानासमुद्र हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशन को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करना है। बांध के निकट मैसूर में दर्शनीय स्थलों मे से एक बृंदावन गार्डन स्थित है।

पूरा कार्य विशेष ध्यान देने की आवश्यकता का होने के कारण, विभागीय पर्यवेक्षण के तहत किया गया था और किसी भी स्तर पर किसी भी ठेकेदार को नियोजित नहीं किया गया था। कार्य की अवधि के दौरान दौरान नियोजित श्रमिकों की संख्या अधिकतम 10,000 तक थी।

हाल ही में, परियोजना पुनर्वास को बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (डीआरआईपी) के तहत शामिल किया गया था। इसके अलावा, बांध के 136 गेटों को बदलने के लिए विस्तृत इंजीनियरिंग परामर्श प्रदान करने के लिए के.ज.आ. द्वारा एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

केंद्रीय जल आयोग
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार का एक सम्बद्ध कार्यालय

संपादक मंडल
- श्री समीर चटर्जी, मुख्य अभियंता (मा.सं.प्र.) - मुख्य संपादक
- श्री अमरेन्द्र कुमार सिंह, मुख्य अभियंता(ईएमओ) - सदस्य
- श्री योगेश पैथंकर, मुख्य अभियंता(पीएमओ) - सदस्य
- श्री दीपक कुमार, निदेशक(नदी प्रबंध समन्वय) - सदस्य
- श्री एस.के. राजन, निदेशक(टीसी) - सदस्य
- श्री भूपिन्द्र सिंह, निदेशक(डब्ल्यूपीएंडपी—सी)- सदस्य
- श्री के.वी. प्रसाद, निदेशक(जल प्रणाली अभि.) - सदस्य
- श्री अर्जेश कुमार मधोक, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य
- श्री आर.के. शर्मा, उप निदेशक(डीएण्डआर सम.) - सदस्य
- श्री शिव सुन्दर सिंह, उप निदेशक(ज.प्र.अभि.) - सदस्य सचिव
- हिन्दी अनुवाद - श्रीमति मीना कुमारी, वरिष्ठ अनुवाद अधिकारी

अभिकल्प एवं प्रकाशन
जल प्रणाली अभियांत्रिकी निदेशालय
केन्द्रीय जल आयोग
द्वितीय तल (दक्षिण) सेवा भवन, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110 066
ई-मेल: media-cwc@gov.in